राजधानी में चर्चित डेवलपर्स बसाएंगे आवासीय कॉलोनी

हाउसिंग बोर्ड के भूखंड व फ्लैट

शहर	कुल भूखंड	आवंटित	अनावंटित
पटना	2550	2236	314
गया	1789	1169	232
भागलपुर	569	414	152
मुजफ्फरपुर	113	25	88
शहर	फ्लैट-मकान	आवंटित	अनावंटित
पटना	6631	5369	1262
भागलपुर	746	618	128
मुजफ्फरपुर	276	103	173

पटना हाउसिंग बोर्ड डाटा

पटना की जनसंख्या **22** लाख

मकानों की संख्या **3** लाख

- सरकार ने देश भर के चुने गये डेवलपर्स के साथ की बैठक
- दीपावली के बाद चार शहरों में शुरू हो जाएगा प्रोजेक्ट

आवास की जरूरत **4.5** लाख

अपार्टमेंटों की संख्या **2600**

टाउनशिप और मिनी टाउनशिप का होगा निर्माण

बोर्ड के प्रबंध निदेश अनुपम कुमार सुमन ने कहा कि राज्य रीयल एस्टेट के क्षेत्र में काफी पीछे है। अभी बोर्ड के पास एक हजार एकड़ जमीन उपलब्ध है जहां व्यावसायिक काम्प्लेक्स का निर्माण और आवासीय कॉलोनियां बसायी जा सकती हैं। वर्तमान में बोर्ड के पास मात्र 75 हजार आवासीय फ्लैट और भूखंड है जिन्हें 1990 के पहले ही बनाया गया है। राज्य के विभिन्न शहरों के आस-पास टाउनशिप और मिनी टाउनशिप बनाया जाना है। मिनी टाउनशिप में कम आयवर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें 40 फीसदी हिस्सा ग्रीन जोन रहेगा। स्कूल, पार्क व कम्युनिटी हॉल का भी प्रबंध रहेगा।

पटना | वरीय संवाददाता

देश भर के चर्चित डेवलपर्स बिहार के चार शहरों में आवासीय कॉलोनियां बसाएंगे। इसके लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड उन्हें अपनी जमीन देगा। चयनित किए गए हर डेवलपर को एक आवासीय कॉलोनी और एक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी।

आवासीय कॉलोनी में घर का आवंटन बोर्ड करेगा जबकि व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में दुकान व कार्यालय आदि का आवंटन डेवलपर्स के माध्यम से होगा। यह जानकारी राज्य सरकार ने मंगलवार को डेवलपर्स के साथ आयोजित एक बैठक में दी। राजधानी के होटल चाणक्या में बिहार राज्य आवास बोर्ड की ओर से आयोजित डेवलपर्स मीट में पूरे देश के 85 डेवलपर्स ने भाग लिया। बैठक में शामिल सभी ने आवास बोर्ड के साथ बिहार में काम करने की इच्छा जाहिर की है। बोर्ड ने भी अपनी विभिन्न परियोजनाओं के बारे में डेवलपर्स को विस्तार से जानकारी दी।

दीपावली के बाद इन डेवलपर्स का चयन कर पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में आवास बोर्ड अपनी जमीन पर उन्हें प्रोजेक्ट शुरू करने की अनुमति देगा। बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि पिछले 40 वर्षों से लोगों को बेहतर आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिए राज्य के दस जिलों में आवास बोर्ड काम कर रहा है। हालांकि हाल के कुछ वर्षों में बोर्ड आवास के क्षेत्र में बेहतर काम नहीं कर सका है। बढ़ती जनसंख्या के मुताबिक आवास के क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। अगले पांच वर्षों में इसकी भरपाई की जाएगी और एक लाख आवासीय यूनिट का निर्माण कराया जाएगा।

तीन वर्ष के अंदर चार शहरों का प्रोजेक्ट हो जाएगा पूरा

विभाग के प्रधान सचिव शशि शेखर शर्मा ने कहा कि शहरों में जमीन खरीदना आम लोगों की बस की बात नहीं रही। ऐसे में मध्यवर्गीय परिवारों को शहर में आवास उपलब्ध करने में बोर्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तीन वर्ष के अंदर पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा।